भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2560

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2560. श्री पुट्टा महेश कुमारः

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

डॉ. कडियम काव्यः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संपूर्ण देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान, उक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का, विशेषकर आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है।

(ग) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की, विशेषकर एलुरु जिले में, राज्य-वार और जिले-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत पूरी की गई, वर्तमान में लंबित और स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का, विशेषकर एलुरु जिले में, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त विनिर्दिष्ट योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार गतिविधियां संपादित की हैं और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजनाओं को उक्तावधि के दौरान कार्यान्वित करते समय निर्धारित और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों का योजना-वार और राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): मंत्रालय चार केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों को क्रियान्वित करता है, इनका उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के साथ-साथ मनोरंजन और शिक्षा के बारे में जनसंचार और सूचना का प्रसार करना है। निधियों का आवंटन न तो राज्य/जिला-वार किया जाता है और न ही लाभार्थी उन्मुख होता है। इन स्कीमों का लाभ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों सहित देश की पूरी जनसंख्या को समान रूप से मिलता है।

सूचना क्षेत्र में, "विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी) स्कीम का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और एकीकृत जन संचार अभियानों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण सुनिश्चित करना है। डीसीआईडी के तहत 2020-21 से 2024-25 तक का बजट परिव्यय 941.31 करोड़ रुपये है।

फिल्म क्षेत्र में, "फिल्मी सामग्री का विकास संचार एवं प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम का उद्देश्य फिल्म समारोहों, फिल्म बाजारों, फिल्मों के निर्माण और राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के माध्यम से अभिलेखीय फिल्मों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना है। डीसीडीएफसी के तहत 2020-21 से 2024-25 तक का बजट परिव्यय 1046.87 करोड़ रुपये है।

प्रसारण क्षेत्र में, "प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास" (बीआईएनडी) स्कीम का उद्देश्य समय-समय पर दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) के प्रसारण अवसंरचना और सामग्री को सुदृढ़ करना है। बीआईएनडी के तहत 2020-21 से 2024-25 तक का बजट परिव्यय 2101 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश राज्य में 16 आकाशवाणी स्टेशन, विजयवाड़ा में एक प्रमुख दूरदर्शन केंद्र और तिरुपति में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा (पीजीएफ) है। तेलंगाना राज्य में 15 आकाशवाणी स्टेशन, हैदराबाद में एक प्रमुख दूरदर्शन केंद्र और वारंगल में एक पीजीएफ है।

इसी तरह, प्रसारण क्षेत्र के तहत "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन" स्कीम का उद्देश्य नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को संसाधनों, क्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ सुदृढ़ करना है, ताकि प्रचालनरत सीआरएस की संख्या और प्रभावशीलता में वृद्धि हो, जो सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देश में 522 सीआरएस हैं, जिनमें से 12 सीआरएस आंध्र प्रदेश में और 9 सीआरएस स्टेशन तेलंगाना में हैं। सीआरएस के तहत 2020-21 से 2024-25 तक का बजट परिव्यय 22.18 करोड़ रुपये है।

*****